

# सह-अस्तित्व से नरसंहार तक: फिलिस्तीन का व्यवस्थित विनाश

19वीं सदी में, ऑटोमन शासन के तहत फिलिस्तीन सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक था। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी—लगभग 25,000 सेफार्डिक और मिजराही यहूदी, जो मुख्य रूप से अरब आबादी के बीच थे—यरुशलम, हेब्रोन और जाफा जैसे शहरों में एक साथ रहते थे। वे बाजारों, पड़ोसों और सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते थे, जिसमें ऑटोमन मिलेट प्रणाली यहूदियों जैसे अल्पसंख्यकों को संरक्षित दर्जा देती थी। हालांकि छोटे-मोटे तनाव उत्पन्न होते थे, हिंसक संघर्ष दुर्लभ थे, और सामाजिक बंधन अक्सर धर्म से परे जाते थे। यह नाजुक शांति एक औपनिवेशिक परियोजना द्वारा चकनाचूर हो गई, जिसने स्वदेशी फिलिस्तीनी बहुसंख्यकों की तुलना में यूरोपीय सायनवादी महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप 77 वर्षों तक विस्थापन, रंगभेद और नरसंहार हुआ।

सायनवादी आंदोलन, जिसे 1897 के सायनवादी कांग्रेस में थियोडोर हर्ज़ल ने औपचारिक रूप दिया, ने 1899 में फिलिस्तीन को एक यहूदी राज्य के लक्ष्य के रूप में घोषित किया, जो यूरोपीय यहूदी-विरोधी भावना और औपनिवेशिक अभिमान से प्रेरित था। यूरोपीय पूंजी द्वारा वित्त पोषित छोटी बस्तियां पूरे फिलिस्तीन में उभरीं, जो अनुपस्थित ऑटोमन जमींदारों से जमीन खरीदकर स्थानीय किसानों को विस्थापित करती थीं। आधुनिक भाषा के रूप में हिब्रू के पुनर्जनन ने एक अलगाववादी पहचान को मजबूत किया, जिसने अरबों के साथ एकीकृत मौजूदा यहूदी समुदायों को अलग-थलग कर दिया। 1917 तक, बाल्फोर घोषणा—जो सायनवादी लॉर्बिस्ट बैरन रोथ्सचाइल्ड द्वारा व्यवस्थित की गई थी—ने ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर को फिलिस्तीन, एक ऐसी भूमि जो देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, को यहूदी मातृभूमि के रूप में देने का वादा किया, जिसने अरब बहुसंख्यकों के अधिकारों और आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया।

1930 के दशक में हावारा समझौते के साथ और अधिक तनाव बढ़ा, जो सायनवादी समूहों और नाज़ी जर्मनी के बीच एक भयावह समझौता था। इसने 60,000 जर्मन यहूदियों और उनकी संपत्तियों को जर्मन सामानों के बदले फिलिस्तीन में स्थानांतरित किया। 1939 तक यहूदी आप्रवासन 450,000 तक बढ़ गया, और इर्गुन और लेही जैसे सायनवादी अर्धसैनिक बलों ने आतंक फैलाया। उनके बम विस्फोट, जैसे 1946 में किंग डेविड होटल पर हमला जिसमें 91 लोग मारे गए, और ब्रिटिश और अरब लक्ष्यों की हत्याओं ने ब्रिटिश जनादेश को अशासनीय बना दिया। 1947 में ब्रिटेन की वापसी ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना को जन्म दिया, एक पूरी तरह से अन्यायपूर्ण योजना जिसने नकबा को प्रज्वलित किया और फिलिस्तीनी पीड़ा के दशकों के लिए मंच तैयार किया।

## संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना का अन्याय

1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना (संकल्प 181) एक औपनिवेशिक विभाजन थी जो न्याय और आत्मनिर्णय को चुनौती देती थी। हालांकि फिलिस्तीनी 67% आबादी (1.2 मिलियन) और यहूदी 33% (600,000) थे, इस योजना ने फिलिस्तीन की 56% भूमि को एक यहूदी राज्य को आवंटित किया, जिसमें उपजाऊ तटीय क्षेत्र और जाफा और हाइफा जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्र शामिल थे। फिलिस्तीनी, जो 94% भूमि के मालिक थे और वहां सदियों से रह रहे थे, को 43% तक सीमित कर दिया गया—वेस्ट बैंक और गाजा में खंडित, कम उपजाऊ क्षेत्र। यह योजना जनसांख्यिकीय वास्तविकता को नजरअंदाज करती थी: यहूदी 7% से कम भूमि के मालिक थे और जाफा को छोड़कर हर जिले में अल्पसंख्यक थे। यरुशलम, एक साझा पवित्र शहर, को एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया, जिसने फिलिस्तीनी दावों को नजरअंदाज कर दिया। अरब बहुसंख्यकों ने इस योजना को उनके अधिकारों का उल्लंघन मानकर अस्वीकार कर दिया, जबकि सायनवादी नेताओं ने इसे अधिक क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए एक कदम के रूप में स्वीकार किया, जैसा कि बाद में उनकी आवंटित सीमाओं से परे विस्तार ने साबित किया। संयुक्त राष्ट्र, जो पश्चिमी शक्तियों द्वारा प्रभुत्व में था, ने फिलिस्तीनियों से परामर्श किए बिना इस विभाजन को थोपा, जो औपनिवेशिक अभिमान को दर्शाता है और स्वदेशी संप्रभुता पर सायनवादी आकांक्षाओं को प्राथमिकता देता है।

## नकबा और उसकी विरासत

1948 में, इजरायल की राज्य की घोषणा ने नकबा—“आपदा” अरबी में—को जन्म दिया। 700,000 से अधिक फिलिस्तीनी, आधे अरब आबादी, को जबरन निष्कासित किया गया या वे आतंक में भाग गए, क्योंकि सायनवादी मिलिशिया ने 500 से अधिक गांवों को नष्ट कर दिया। देयर यासीन जैसे नरसंहार, जहां 100 से अधिक नागरिकों की हत्या की गई, ने भय को मजबूत किया। फिलिस्तीनियों को गाजा, वेस्ट बैंक और जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में शरणार्थी शिविरों में खदेड़ दिया गया, और उन्हें वापस लौटने से रोक दिया गया। इस नस्लीय सफाई को, योसेफ वीट्ज जैसे व्यक्तियों द्वारा सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया था, जो यहूदी राष्ट्रीय कोष के एक अधिकारी थे, जिन्होंने 1940 में घोषणा की थी, “इस देश में दोनों लोगों के लिए कोई जगह नहीं है... एकमात्र समाधान एक फिलिस्तीन है... बिना अरबों के,” जिसने इजरायल के रंगभेदी राज्य की नींव रखी। वीट्ज की जबरन “हस्तांतरण” की दृष्टि ने नकबा की क्रूरता को आकार दिया और फिलिस्तीनी निशस्त्रीकरण में आज भी गूंजती है।

## वेस्ट बैंक में निशस्त्रीकरण और विस्थापन

1967 में इजरायल के वेस्ट बैंक पर कब्जे के बाद से, निशस्त्रीकरण निरंतर रहा है। अब 700,000 से अधिक इजरायली बसने वाले अवैध बस्तियों में रहते हैं, जो चुराई गई फिलिस्तीनी जमीन पर बनाई गई हैं, जिसने वेस्ट बैंक को असंबद्ध एन्क्लेव में विभाजित कर दिया है। इजरायल की नीतियां—जमीन की जब्ती, घरों का विध्वंस और प्रतिबंधात्मक परमिट—ने दसियों हजार लोगों को विस्थापित किया है। बी’त्सेलेम के अनुसार, 1967 के बाद से 20,000 से अधिक फिलिस्तीनी घरों को ध्वस्त किया गया है, अक्सर परमिट की कमी जैसे बहाने के तहत, जो इजरायल शायद ही कभी प्रदान करता है। जॉर्डन घाटी और पूर्वी यरुशलम जैसे क्षेत्रों में, पूरे समुदाय निष्कासन का सामना कर रहे हैं; उदाहरण के लिए, मसाफर यट्टा के 1,000 निवासियों को सैन्य क्षेत्रों के विस्तार के लिए हटाने की धमकी दी गई है। बस्तियों का विस्तार, जो इजरायली कानून और सैन्य सुरक्षा द्वारा समर्थित है, ने वेस्ट बैंक की 40% से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसमें फिलिस्तीनी 165 “द्वीपों” में सख्त नियंत्रण के तहत सीमित हैं। चेकपोइंट, सड़क अवरोध और अलगाव की दीवार—जो 2004 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अवैध घोषित की गई थी—परिवारों, कृषि भूमि और आजीविका को अलग करती है, जिससे फिलिस्तीनी जीवन असहनीय हो जाता है। यह व्यवस्थित चोरी, निर्माण अधिकारों की अस्वीकृति के साथ मिलकर, विस्थापन को मजबूर करती है और रंगभेद को मजबूत करती है।

## वेस्ट बैंक में बसने वालों की हिंसा

वेस्ट बैंक में इजरायली बसने वालों की हिंसा एक दैनिक आतंक है, जो राज्य की मिलीभगत से संभव हुई है। बसने वाले, अक्सर सशस्त्र और इजरायली बलों द्वारा संरक्षित, फिलिस्तीनी किसानों, चरवाहों और गांवों पर हमला करते हैं ताकि उन्हें उनकी जमीन से भगा सकें। केवल 2024 में, संयुक्त राष्ट्र ने 1,200 से अधिक बसने वाले हमलों को दर्ज किया, जिसमें आगजनी, बर्बरता और शारीरिक हमले शामिल हैं। हवारा और कुसरा जैसे गांवों में, बसने वालों ने घरों, जैतून के बागों और पशुओं को जला दिया, जिसमें 2023 के हवारा नरसंहार जैसे घटनाओं में एक फिलिस्तीनी की मृत्यु हुई और सैकड़ों घायल हुए। इजरायली सैनिक अक्सर निष्क्रिय रहते हैं या स्वयं को बचाने वाले फिलिस्तीनियों के खिलाफ हस्तक्षेप करते हैं। बी’त्सेलेम की रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य चौकियों द्वारा समर्थित बसने वालों ने फिलिस्तीनियों के लिए “प्रवेश निषिद्ध क्षेत्र” बनाए हैं, हिंसा के माध्यम से हजारों एकड़ जमीन हड़प ली है। हिलटॉप यूथ जैसे चरमपंथी बसने वाले समूह खुले तौर पर फिलिस्तीनियों को निष्कासित करने का लक्ष्य रखते हैं, जो बेज़ालेल स्मोट्रिच जैसे सरकारी व्यक्तियों द्वारा प्रोत्साहित होते हैं, जो बस्ती नीति की देखरेख करते हैं और फिलिस्तीनी “अधीनता” की मांग करते हैं। यह हिंसा, जो शायद ही कभी अभियोगित होती है, नस्लीय सफाई का एक उपकरण है, जो फिलिस्तीनी अस्तित्व को अनिश्चित बनाती है।

## नरसंहार की बयानबाजी और कार्रवाइयां

इजरायली नेताओं की बयानबाजी ने लंबे समय से फिलिस्तीनियों को अमानवीय बनाया है, जिससे अत्याचारों को उचित ठहराया गया है। 1940 में योसेफ वीट्ज का अरब-मुक्त फिलिस्तीन का आह्वान दशकों बाद उवाडिया योसेर एड्टान जैसे व्यक्तियों द्वारा दोहराया गया, जो एक पूर्व जनरल थे, जिन्होंने 1983 में फिलिस्तीनियों को “नशे में धुत तिलचट्टों” से तुलना की, जो उनके नजरबंदी और विनाश के लिए एक घृणित रूपक था। हाल ही में, अक्टूबर 2023 में, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने

गाजा पर “पूर्ण घेराबंदी” लागू की, और घोषणा की, “कोई बिजली नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई ईंधन नहीं... हम मानव पशुओं से लड़ रहे हैं।” वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच, जो गाजा के पूर्ण विनाश की वकालत करते हैं, ने 2023 में कहा कि “गाजा को मिटाना” आवश्यक था, और भुखमरी और बमबारी का समर्थन किया। ये बयान, जैसे कि घेराबंदी और निरंतर हवाई हमलों जैसे कार्यों के साथ, संयुक्त राष्ट्र की नरसंहार की परिभाषा के अनुरूप हैं: एक समूह को नष्ट करने के लिए जानबूझकर किए गए कार्य। यरुशलम ध्वज मार्च, 1967 से एक वार्षिक आयोजन, में हजारों इजरायली अतिनातिवादी, जिसमें बसने वाले शामिल हैं, पूर्वी यरुशलम के माध्यम से “अरबों को मौत” के नारे लगाते हैं, जो एक नफरत का अनुष्ठान है जिसे पुलिस द्वारा संरक्षित किया जाता है। 2024 में, मार्च के प्रतिभागियों ने फिलिस्तीनी दुकानों और पत्रकारों पर हमला किया, बिना किसी महत्वपूर्ण परिणाम के, जिसने नरसंहार की भावनाओं को सामान्य किया।

## गाजा में चल रहा नरसंहार

गाजा, 2 मिलियन लोगों के लिए 365 वर्ग किलोमीटर का जेल, निरंतर भयावहता का सामना कर रहा है। अक्टूबर 2023 से, इजरायली सेना ने 60,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है—70% महिलाएं और बच्चे—गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार। गैलेंट और स्मोट्रिच की घेराबंदी ने 80% गाजावासियों को भुखमरी में डाल दिया है, जिसमें 1.8 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं (संयुक्त राष्ट्र, 2025)। गाजा मानवतावादी फाउंडेशन के सहायता स्थल, जो 2025 में स्थापित किए गए थे, मृत्यु के जाल हैं: 743 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और 4,891 घायल हुए, अक्सर इजरायली गोलीबारी और बमबारी द्वारा, भोजन की तलाश में। एमनेस्टी इंटरनेशनल और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इन कृत्यों को संभावित युद्ध अपराध कहते हैं, और संयुक्त राष्ट्र इजरायल की भुखमरी नीति को नरसंहार के रूप में लेबल करता है। अस्पताल, स्कूल और शरणार्थी शिविर खंडहरों में हैं, जिसमें गाजा की 90% बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। क्रूरता—बच्चों को गोली मारना, परिवारों को मलबे के नीचे दफन करना, और भीड़ का नरसंहार—एक लोगों को मिटाने की सुनियोजित मंशा को दर्शाती है।

## निष्कर्ष

19वीं सदी के सह-अस्तित्व से आज के नरसंहार तक, फिलिस्तीन की कहानी औपनिवेशिक चोरी, विश्वासघात और निरंतर क्रूरता की कहानी है। संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना का अन्याय, नकबा की नस्लीय सफाई, और वेस्ट बैंक में चल रहे निशस्त्रीकरण और बसने वालों की हिंसा दमन का एक सातत्य बनाते हैं। वीट्ज से गैलेंट तक की नरसंहार की बयानबाजी, “अरबों को मौत” के नारों द्वारा बढ़ाई गई, एक ऐसी प्रणाली को पोषित करती है जो फिलिस्तीनी पीड़ा पर फलती-फूलती है। गाजा में नरसंहार, जिसमें 60,000 से अधिक मृत्यु हुईं, केवल एक त्रासदी नहीं है बल्कि मानवता के खिलाफ एक अपराध है, जो वैश्विक चुप्पी द्वारा संभव हुआ है। फिलिस्तीनी संघर्ष न केवल स्मृति की मांग करता है, बल्कि न्याय की भी।